महेश ग्रोवर जे. के समक्ष

इंदर सैन और अन्य, - अपीलकर्ता/वादी
बनाम
टीका राम और अन्य,-प्रतिवादी/प्रतिवादी
RSA No. 1983 का 2394
1 अप्रैल, 2010

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - संयुक्त हिंदू परिवार - संयुक्त फर्म के खातों के विभाजन और प्रतिपूर्ति की मांग करने वाले पुत्र - क्या कोई व्यक्ति अपने पिता के जीवनकाल के दौरान संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के विभाजन की मांग कर सकता है - मुकदमे के लंबित रहने के दौरान पिता की मृत्यु - बदली हुई परिस्थितियों के कारण जब पिता मृत्यु हो गई और वादी नंबर 3 की भी मृत्यु हो गई, उसके कानूनी प्रतिनिधियों को मृतक-वादी नंबर 3 के उत्तराधिकारी होने के नाते, संयुक्त संपत्ति के विभाजन की मांग करने का हकदार माना गया।

अभिनिर्धारित किया कि, यह दिखाने के लिए कोई लेखन नहीं था कि वादी संख्या 3-सत नारायण संयुक्त परिवार से अलग हो गए थे। प्रतिवादी यह साबित करने में भी असफल रहे कि विचाराधीन संपत्ति व्यक्तिगत निधि से टीका राम या राम किशन से खरीदी गई थी। इसलिए, मामले के इस पहलू पर प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष सही हैं और बरकरार रखे जाने योग्य हैं। ऐसी स्थिति में, जब वादी संख्या 3 का दावा केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि पिता जीवित थे, मेरी राय है कि बदली हुई परिस्थितियों के कारण जब टीका राम ने स्वीकार कर लिया है कि मृत्यु हो गई है और यहां तक कि वादी भी समाप्त हो गया है, तो उसका इसलिए, कानूनी प्रतिनिधि मृतक-वादी संख्या 3-सत नारायण के हित में उत्तराधिकारी होने के नाते, संयुक्त संपत्ति के विभाजन की मांग करने के हकदार हैं।

(पैरा 14 एवं 16)

इसके अलावा, माना गया कि दुकान के वादी-सत नारायण और प्रतिवादियों की संयुक्त संपत्ति होने के संबंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों को बरकरार रखा गया है और यह भी माना गया है कि वादी-सत नारायण के कानूनी प्रतिनिधि इसके विभाजन की मांग करने के हकदार हैं। साथ ही उससे चलायी जा रही फर्म के खातों का विवरण भी।

(पैरा 8)

निमो, अपीलकर्ताओं के लिए।

विजय पाल सिंह, वकील, प्रतिवादी नंबर 3, सत नारायण के एल.आर.एस. के लिए।

अन्य उत्तरदाताओं के लिए कोई नहीं.

(2) 198 3 का आर.एस.ए. क्रमांक 2436

अपीलकर्ताओं के लिए निमो।

विजय पाल सिंह, वकील, प्रतिवादी नंबर 1, सत नारायण के एल.आर.एस. के लिए।

अन्य उत्तरदाताओं के लिए कोई नहीं.

(3) l984का आर.एस.ए. क्रमांक 542

अपीलकर्ता के एल. की ओर से विजय पाल सिंह, अधिवक्ता।

अन्य उत्तरदाताओं के लिए कोई नहीं.

महेश ग्रोवर, जे.:-

(1) यह सामान्य निर्णय उपर्युक्त तीन अपीलों का निपटान करेगा जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जींद (इसके बाद 'प्रथम अपीलीय न्यायालय' के रूप में वर्णित) द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 19.9.1983 के खिलाफ दायर की गई हैं।

(2) वादी इंदर सैन , साधु राम और सत नारायण ने अपने पिता- टीका राम और भाई- राम किशन के खिलाफ घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया था , इस आशय से कि जिस दुकान का वर्णन वाद के पैराग्राफ 2 (ए) में किया गया था। इसका स्वामित्व संयुक्त हिंदू परिवार के पास है जिसमें स्वयं और प्रतिवादी शामिल हैं। उन्होंने आगे उक्त दुकान और संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यापारिक फर्म - मेसर्स टीका राम नंद किशोर, जिसे पहले मेसर्स साधु राम नंद किशोर के नाम से जाना जाता था, सहित अन्य संपत्तियों के विभाजन की डिक्री की मांग की। उक्त फर्म के खातों के प्रतिपादन की डिक्री के लिए भी प्रार्थना की गई थी। संयुक्त हिंदू परिवार के स्वामित्व वाली संपत्तियों का विवरण भी वादपत्र में दिया गया था। यह फर्म संबंधित दुकान में कपड़ा बेचने के व्यवसाय में लगी हुई बताई गई थी और यह व्यवसाय 1966 से अस्तित्व में था। टीका राम को परिवार का कर्ता बताया गया था, लेकिन उनकी वृद्धावस्था के कारण, राम किशन-प्रतिवादी ने इनकार कर दिया। .1 को कर्ता के रूप में कार्य करने वाला बताया गया। यह आरोप लगाया गया था कि

संबंधित दुकान संयुक्त परिवार के अन्य व्यापारिक हितों से खरीदी गई थी और हालांकि, इसे टीका राम के नाम पर खरीदा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और राम किशन के नाम पर खरीदी गई थी। जो परिवार के कर्ता के रूप में कार्य कर रहा था। यह आरोप लगाया गया था कि इस तथ्य को कई वर्षों तक वादी से छुपाया गया था और चूंकि, विवाद में दुकान पर राम किशन का विशेष कब्जा था, इसलिए उन्होंने संयुक्त हिंदू परिवार की अन्य संपत्तियों के साथ-साथ खातों के प्रस्तुतिकरण के साथ इसके विभाजन की प्रार्थना की। फर्म-मैसर्स टीका राम नंद किशोर की।

(3) प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयान में, पार्टियों के रिश्ते से इनकार नहीं किया, लेकिन दलील दी कि उनके बीच विभाजन पहले ही हो चुका है और विवाद में दुकान में वादी का कोई जीवित हित नहीं है, जो अन्य संपत्तियों के साथ विभाजित हो गया था। परिवार की। उनके द्वारा अपने पक्ष में एक त्याग विलेख स्थापित किया गया था जिसे कथित तौर पर वादी द्वारा निष्पादित किया गया था। संपत्तियों की पैतृक प्रकृति को भी स्वीकार किया गया।

(4) कई मुद्दे तय किए गए और पार्टियों ने अपने-अपने साक्ष्य पेश किए।

(5) वरिष्ठ उप न्यायाधीश, जिंद (बाद में इसे 'ट्रायल कोर्ट' के रूप में वर्णित किया गया है) ने निष्कर्ष निकाला कि विचाराधीन दुकान पक्षों के बीच संयुक्त रूप से जारी रही और इसके लिए कोई विभाजन नहीं हुआ। इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 30.11.1981 के निर्णय और डिक्री द्वारा प्रार्थना के अनुसार मुकदमे का फैसला सुनाया। इसलिए, वादी के पक्ष में एक प्रारंभिक डिक्री पारित की गई और दोनों पक्षों में से किसी एक को विभाजन को प्रभावित करने के साथ-साथ खातों के प्रस्तुतिकरण के लिए स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई।

(6) प्रतिवादियों ने व्यथित महसूस करते हुए एक अपील दायर की जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया गया। संयुक्त हिंदू परिवार फर्म साधु राम नंद किशोर के बंटवारे और खातों के पुनर्भुगतान के वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया गया। हालाँकि, वादी संख्या का मुकदमा। 1 और 2 को इस आशय से कि उन्होंने अपने पिता के साथ संयुक्त हिंदू परिवार का गठन किया, भी खारिज कर दिया गया। वादी संख्या 3-सत नारायण का वाद इस आशय का था कि वह अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त था, फैसला सुनाया गया। वादपत्र के पैरा 2(ए) में वर्णित दुकान को भी संयुक्त हिंदू परिवार का हिस्सा घोषित किया गया था, जिसका

गठन वादी संख्या 3 प्रतिवादियों के साथ कर रहा था। वादपत्र के पैराग्राफ 2(बी), (सी) और (डी) में वर्णित अचल संपत्ति के विभाजन की डिक्री भी वादी संख्या के पक्ष में पारित की गई थी। 1 एवं 2 तथा उनमें उनका हिस्सा 1/5 प्रत्येक के रूप में निर्धारित किया गया था। ट्रायल कोर्ट को विभाजन के तरीके का सुझाव देने के लिए एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया था।

(7) विभाजन के लिए वादी-सत नारायण के दावे को अस्वीकार करने के लिए, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया था, जिसे **हरि किशन बनाम चंदू लाल** , 1917 सिविल जजमेंट नंबर 105, पृष्ठ 408 के रूप में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें यह कहा गया था। यह माना गया कि पंजाब में लागू हिंदू कानून के तहत, एक बेटे को विभाजन का दावा करने या अपने पिता से हिसाब मांगने का कोई अधिकार नहीं है।

(8) प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट, वादी सं. 1 और 2, यानी, इंदर सैन और साधु राम ने 1983 का RSANo.2394 दायर किया, प्रतिवादियों - टीका राम और राम किशन ने 1983 का RSANo.2436 दायर किया, जबकि वादी संख्या 3-सत नारायण ने 1984 का RSANo.542 दायर किया।

(9) अपीलों के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी संख्या 1- वादी और प्रतिवादी संख्या 2 के पिता टीका राम की 17.2.1982 को मृत्यु हो गई।

(10) वादी संख्या 1- इंदर सैन और वादी संख्या 3-सत नारायण की भी मृत्यु हो गई और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाया गया।

(11) सुनवाई में, श्री विजय पाल सिंह, वकील वादी संख्या 3-सत नारायण के कानूनी प्रतिनिधियों के लिए उपस्थित हुए। अन्य दलों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

(12) मैंने श्री सिंह को सुना है और पूरा रिकार्ड देखा है। उनके द्वारा तर्क दिया गया था कि विचाराधीन संपत्ति संयुक्त है और वादी-सत नारायण के विभाजन की मांग करने के रास्ते में एकमात्र बाधा यह थी कि उनके पिता जीवित थे जिनके जीवनकाल के दौरान विभाजन और खातों का हिंदू के अनुसार दावा नहीं किया जा सकता था। पंजाब राज्य में खत्रियों पर लागू कानून। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय अदालत ने **हरि किशन बनाम चंदू लाल** (सुप्रा) में पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा करके इस सीमित पहलू पर विचार करके ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को खारिज कर दिया है। यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि पिता की मृत्यु हो गई है, वादी-सत नारायण और अब उनके कानूनी प्रतिनिधि फर्म के बंटवारे के साथ-साथ खातों का प्रतिपादन करने के हकदार हैं।

(13) वादी-सत नारायण के कानूनी प्रतिनिधियों के विद्वान वकील के तर्क/प्रस्तुतीकरण आकर्षक और स्वीकार्य प्रतीत होते हैं। विवाद उस दुकान के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसकी बात हो रही है. अन्य संपत्तियों को ऊपर वर्णित पार्टियों के शेयरों के अनुसार विभाजित किया गया माना गया है।

(14) मुकदमे की संपत्ति वादी-सत नारायण और प्रतिवादियों की संयुक्त होने के संबंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष को सही ढंग से दर्ज किया गया है क्योंकि यह पाया गया है और रिकॉर्ड पर स्थापित किया गया है कि वादी संख्या 1 और 2 संयुक्त व्यवसाय से अलग हो गए थे क्रमशः वर्ष 1952 और 1964। उस आशय के लेख रिकॉर्ड पर साबित हुए थे। यहां तक कि राम किशन-प्रतिवादी नंबर 2 ने भी उपरोक्त आशय को DW1 के रूप में पेश होते हुए स्पष्ट रूप से कहा है। उन्होंने कहा था कि पहले संबंधित दुकान चारों भाइयों की संयुक्त दुकान थी जिसे उनके पिता टीका राम , जो परिवार के कर्ता हैं, चलाते थे। बेशक, यह दिखाने के लिए कोई लेखन नहीं था कि वादी संख्या 3-सत नारायण संयुक्त परिवार से अलग हो गए थे। प्रतिवादी यह साबित करने में भी विफल रहे कि विचाराधीन संपत्ति टीका राम या राम किशन के व्यक्तिगत फंड से खरीदी गई थी। इसलिए, मामले के इस पहलू पर प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष सही हैं और बरकरार रखे जाने योग्य हैं।

(15) ऐसी स्थिति में, जब वादी-सत नारायण का दावा केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि पिता जीवित थे, मेरी राय है कि बदली हुई परिस्थितियों के कारण जब टीका राम ने स्वीकार कर लिया है कि मृत्यु हो गई है और यहां तक कि वादी-सत नारायण भी समाप्त हो गया है, इसलिए, उनके कानूनी प्रतिनिधि, मृतक-सत नारायण के उत्तराधिकारी होने के नाते, संयुक्त संपत्ति के विभाजन की मांग करने के हकदार हैं।

(16) इसलिए, कानून का प्रश्न, जो इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए उठता है, वह यह है कि 'क्या कोई व्यक्ति अपने पिता के जीवन काल के दौरान संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के विभाजन की मांग कर सकता है?'

(17) **हरि किशन बनाम चंदू लाल** (सुप्रा) में पूर्ण पीठ ने माना है कि भले ही हिंदू कानून की मिताक्षरा प्रणाली के तहत, एक बेटा अपने पिता के जीवन काल के दौरान संपत्ति के बंटवारे की मांग कर सकता है, लेकिन पंजाब में यह सख्त हिंदू कानून का नियम है। कानून लागू नहीं है और पंजाब के खत्रियों के बीच यह दायित्व है कि वे पिता के जीवनकाल के दौरान संयुक्त परिवार की संपत्ति के बंटवारे की मांग नहीं कर सकते। सख्त व्याख्या यह है कि हिंदू कानून की मिताक्षरा प्रणाली के

अनुसार, एक बेटा संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के विभाजन को लागू कर सकता है, लेकिन, प्रतिवादी नंबर 1 की मृत्यु से उत्पन्न बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए कानून के इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। - टीका राम . अत: इस पहलू पर और अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

(18) ऊपर जो कहा गया है, उसके आधार पर, दुकान के वादी-सत नारायण और प्रतिवादियों की संयुक्त संपत्ति होने के संबंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष को बरकरार रखा गया है और आगे यह माना जाता है कि वादी-सत नारायण के कानूनी प्रतिनिधि नारायण उसके विभाजन के साथ-साथ उससे चलाई जा रही फर्म के खातों का विवरण मांगने के हकदार हैं।

(19) तदनुसार, वादी-सत नारायण की अपील स्वीकार की जाती है, जबकि वादी संख्या की अपील। 1 और 2 - इंदर सैन (मृतक के बाद से) और साधु राम के साथ-साथ प्रतिवादियों को बर्खास्त किया जाता है।

R.N.R.

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नीतिका बांसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा